

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2010—कार्तिक 27, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन के आदेश जारी किये गये, दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/2002 एस. आर. (एस) दिनांक 1-5-2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में मध्यप्रदेश शासन से सहमति पश्चात् भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 29-04-2005 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 20-05-2005 को जारी किये गये, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई एवं अंतिम बार दिनांक 30-06-2010 तक बढ़ाई गई थी.

2. दोनों राज्यों की सहमति उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिवारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य की सेवा के राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी यदि आपसी अदला बदली चाहते हैं तो दोनों राज्यों के प्रशासकीय विभाग की सहमति उपरान्त छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से दिनांक 31 मार्च 2011 तक कैडर स्थानांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी. उक्त अवधि के पश्चात् राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

